

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1609/2011/भीलवाडा
मैसर्स बी. सिन्हैया एण्ड कम्पनी प्रोजेक्ट लिमिटेड
भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

प्रभारी, चेक पोस्ट
घाटोली, झालावाडा

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री एम.एल.पाटोदी एवं ईशू जैन
अभिभाषक
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 29.09.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 127/आरएसटी/06-07 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा उन्होंने प्रभारी, चेक पोस्ट, घाटोली जिला झालावाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,57,229/- आरोपित की है, को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 19.11.2006 को वाहन संख्या आर जे 06 जी 0085 की जांच करने पर पाया गया कि देवरी कला जिला सागर, मध्य प्रदेश से माल राज्य में आ रहा था। वक्त जांच माल के साथ चालान एवं ट्रांसफर मीमो थे परन्तु घोषणा पत्र एस टी 18सी नहीं होने से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,57,229/- आरोपित कर दी। उक्त आरोपित शास्ति के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अपील अस्वीकार कर आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी फर्म द्वारा देवरी कला जिला सागर, मध्य प्रदेश में ठेका लिया है, जिसको पूर्ण करने के लिए राज्य के माल का स्थानान्तरण राजस्थान राज्य से देवरी कला जिला सागर, मध्य प्रदेश के लिए किया था। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग माल के साथ स्थानान्तरण मीमो एवं चालान संलग्न था जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा था " NOT FOR SALE, SITE



TRANSFER" जिसके साथ वैट-49 घोषणा पत्र संलग्न था। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने चेक पोस्ट घालोची पर माल को डिटेन किया तथा नोटिस जारी कर पूछा गया कि माल के साथ घोषणा पत्र 18 सी क्यों नहीं है ? उनका कथन है कि नोटिस प्राप्त होने पर, उसके जवाब के साथ घोषणा पत्र 18सी संख्या 0903825 दिनांक 29.11.2006 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त घोषणा पत्र पर विचार किये बिना ही दिनांक 30.11.2006 को आदेश पारित कर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रु.1,57,229/- आरोपित कर दी, जो अविधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.11.2006 की पुष्टि की है, जो अविधिक है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2282/2010/कोटा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन घट प्रथम, वृत्त-तृतीय, राज. जयपुर बनाम मैसर्स कृष्णा सेल्स कारपोरेशन, कोटा में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2013 प्रस्तुत कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र 18सी नहीं पाया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने माल परिवहन के समय उसके साथ घोषणा प्रपत्र 18सी होना आज्ञापक माना है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल के साथ घोषणा प्रपत्र 18सी नहीं होने के कारण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कारण बताओ नोटिस जारी करने पर जवाब के साथ घोषणा प्रपत्र 18सी संख्या 0903825 पेश किया गया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उसे अमान्य करते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,57,229/- आरोपित की है, जिसको अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2010 पारित कर आरोपित शास्ति को यथावत रखा है।

बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2282/2010/कोटा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन घट प्रथम, वृत्त-तृतीय, राज. जयपुर बनाम मैसर्स कृष्णा सेल्स कारपोरेशन, कोटा में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2013 को उद्धृत किया है जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक



वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पार्ट-2 पेज 49 एवं मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता बांसवाडा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित न्यायिक दृष्टान्तों को उद्धृत करते हुए नोटिस के जवाब के साथ यदि वांछित घोषणा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्त्रि को अपास्त किया गया है। उक्त निर्णय का सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

"माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पार्ट-2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case it is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता बांसवाडा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".....On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."


"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and



no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति उचित नहीं है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2010 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य